भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1445

23 सितम्बर, 2020 को उत्तरार्थ

विषय: कोविड-19 परिस्थिति से निपटने के लिए किसानों को सहायता प्रदान करना

1445 श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि कई प्रवासी मज़दूर जो कोविड-19 लॉकडाउन के कारण अपने-अपने गांव को लौटने के लिए मजबूर हुए थे, ने अब उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ऐसे लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए क्या-क्या कदम उठा रही है;

(ग) सरकार कोविड -19 संकट के अगले कुछ महीनों के दौरान किसानों को किस प्रकार से सहायता प्रदान करने का विचार रखती है;

(घ) क्या कोविड -19 लॉकडाउन के कारण मार्च, 2020 के बाद किसानों की आत्महत्या के कोई मामले सामने आए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार की आत्महत्याओं की कुल संख्या कितनी है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क) से (ग): ऐसी कोई भी आय मूल्यांकन रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है जिससे किसानों की आय में कोरोना वायरस के पड़े प्रभाव का आकलन लगाया जा सके।

सरकार ने देशभर में किसानों के कल्याण के लिए कोविड-19 विश्वमहामारी लॉकडाउन के दौरान निम्नलिखित गतिविधियां सक्रियता के साथ की हैं-

i. 'आत्मनिर्भर भारत' के लिए 20 लाख करोड़ रूपये का पैकेज आवंटित करना जिसमें एक लाख करोड़ रूपये का कृषि अवसंरचना निधि सृजन तथा 500 करोड़ रूपये मधुमक्खी पालन का भी शामिल है।

ii. कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) अध्यादेश, 2020 तथा कृषक (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अध्यादेश, 2020 नामक दो अध्यादेशों को लागू करना।

iii. पीएम-किसान स्कीम के अंतर्गत 24 मार्च, 2020 से किसानों के बैंक खातों में 40000 करोड़ रूपये जमा किए गए हैं।

iv. सरकार ने पूरी फसल के समय पर तैयार होने के लिए किसानों को सुविधाएं प्रदान कीं जिसके परिणामस्वरूप रबी फसल उत्पादन की रिकार्ड खरीद की गई।

v. पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में खरीफ फसलों के बुवाई क्षेत्र के कवरेज में 5.68% की वृद्धि हुई है।

vi. थोक मण्डियों की भीड़-भाड़ को कम करने तथा ई-नाम को ई-एनडब्ल्यूआर के साथ जोड़ने, एफपीओ को पास/ई-पास जारी करवाने, कृषि उत्पादों का तेजी से ढुलाई करने के लिए किसानों को ढुलाई हेतु सामूहिक रूप से उबराइजेशन मॉडयूल ऑफ लॉजिस्टिक आरंभ करने, आवश्यक समानों तथा फलों एवं सब्जियों की आपूर्ति एवं कीमतों की निगरानी करने के लिए विभाग में अलग से एक प्रकोष्ठ का गठन करने संबंधी अनेकों गतिविधियां आरंभ की गई थीं। 1000 एफपीओ के उन्नयन के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम का गठन एवं अनुमोदन, किसान रथ मोबाईल ऐप एवं फार्म मशीनरी मोबाईल ऐप को आरंभ किया गया।

vii. किसान, मण्डी एवं उपभोक्ताओं के बीच बाधारहित सम्पर्क स्थापित करने के लिए तथा समयबद्ध आधार पर अंतरराज्यीय मण्डियों में शीघ्र नष्ट होने वाले कृषि उत्पादों को भेजने के लिए किसानों की सहायता हेतु किसान रेल आरंभ की गई।

viii. खरीद केंद्र बढ़ाए गए।

(घ) से (ङ): गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) "भारत में दुर्घटनावश मृत्यु और अत्महत्या (एडीएसआई)" शीर्षक के प्रकाशन में आत्महत्या की सूचना का संकलन और प्रसारण करता है। वर्ष 2019 तक की आत्महत्याओं पर ये रिपोर्ट इसकी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

****